



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2011/ज्येष्ठ 5, 1933

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2011/JYAISTHA 5, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2011

सं. 35/2011-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 409(अ).—जहां कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म के विनिर्माताओं द्वारा आयात किये गये माल के रियायती दरों पर आयात की अनुमति अधिसूचना सं. 25/99-सीमा-शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999, जिसे सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना सं. 25/2002-सीमा-शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था (जिनमें अधिसूचना सं. 8/2004-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 जनवरी, 2004 जिसे सा.का.नि. 21(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना सं. 71/2004-सीमा-शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2004, जिसे सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है), के द्वारा उस समय दी गई है जब इनका आयात मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने के लिये या इनके लिये किया गया हो और यह अनुमति सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्क के माल के विनिर्माण के लिये शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996 के अंतर्गत विनिर्धारित प्रक्रिया के अधीन है;

और जहां कि मेटेक्स (इंडिया) प्रा.लि.-बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली के मामले में 1998 की सिविल अपील सं. 3224-3225, 1998 की सीए सं. 5716 सहित, में दिनांक 12 फरवरी, 2004 को दिये गये निर्णय, जिसमें यह कहा गया है कि प्लास्टिक फिल्म के धातवीकरण की प्रक्रिया को विनिर्माण नहीं माना जा सकता है, के अनुसार ऐसे माल पर सीमा-शुल्क की उच्चतर दर लगाई जाती है;

और जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी प्रथा के अनुसार जो कि शुल्क के लागू किये जाने के बारे में सामान्यतया प्रचलन में है (उसके गैर-लेवी समेत) उक्त माल को उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर पर आयात किये जाने की अनुमति दी जाती रही और ऐसे माल पर सीमा-शुल्क की उस दर से ज्यादा शुल्क लगाया गया है जो कि उक्त प्रथा के अनुसार लगाया जाना चाहिए;

अतः, अब, उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के बावजूद सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त प्रथा के अनुसार लगाये जाने वाले सीमा-शुल्क से जितना अधिक सीमा-शुल्क लगाया गया है उसका उन माल के बारे से भुगतान किये जाने की जरूरत नहीं है जिन पर उक्त प्रथा के अनुसार शुल्क कम लगाया गया था, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, यथा—

- (क) उक्त माल का आयात 12 फरवरी, 2004 से पहले किया गया हो;
- (ख) उक्त माल का प्रयोग उस अंतिम उत्पाद के लिए या उसके उत्पादन में किया गया हो जिन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया हो;
- (ग) अंतिम उत्पाद पर भुगतान किये गये शुल्क को उक्त विनिर्माता द्वारा वापस न लिया गया हो ।

[फा. सं. 528/24/2010-एस टी ओ (टी यू)]

विकास, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2011

**No. 35/2011-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 409(E).**—Whereas it appears that the goods imported by manufacturers of metallised plastic films were allowed to be imported at concessional rates of duty by virtue of Notification No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 261(E), dated the 28th February, 1999 and Notification No. 25/2002-Customs, dated 1st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 122 (E), dated the 1st March, 2002 (as amended by Notification No. 8/2004-Customs dated 8th January, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 21(E), dated the 8th January, 2004 and Notification No. 71/2004-Customs dated 9th July, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 9th July, 2004, when imported for use in or for the manufacture of metallised plastic films, subject to the procedure laid down under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996;

And whereas such goods have been rendered liable to higher rate of duty of customs by virtue of the judgement of the Supreme Court in Civil Appeal Nos. 3224-3225 of 1998 with C.A. No. 5716 of 1998 decided on the 12th February, 2004, in the case of Meltex (India) Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Central Excise, New Delhi, holding the process of metallisation of plastic film as not amounting to manufacture;

And whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof), the said goods were being allowed to be imported at concessional rate of duty under the said notifications and that such goods have been rendered liable to higher rate of duty of customs than what was levied according to the said practice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28A of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government, hereby, directs that the duties of customs in excess of that payable but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the duty was short-levied in accordance with the said practice, notwithstanding the said judgment of the Supreme Court subject to following conditions, namely :—

- the said goods were imported prior to 12th February, 2004;
- the said goods have been used in or for production of final products on which duty of excise has been paid;
- no refund of duty of excise paid on the said final products has been availed by the said manufacturer.

[ F. No. 528/24/2010-STO(TU) ]

VIKAS, Under Secy.